



खबर पेज 7 पर



गंभीर समाचार

समय-समाज-संस्कृति



खबर पेज 8 पर

वर्ष -11 अंक-14

पाक्षिक समाचार पत्रिका

कोलकाता, बुधवार 1 - 15 अक्टूबर 2025

मूल्य: 5 रुपये

RNI No.WBHIN/2014/59321, ISSN No. 2456/3005 Kolkata

कुल पृष्ठ - 8

सुविचार

- ♦लहरोँ और समय किसी के लिए भी रुकते नहीं हैं।
- ♦इंसान सफल तब होता है जब वो जरूरत और चाहत के बीच फर्क समझ लेता है।
- ♦अगर जिन्दगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो!!
- ♦अगर आप किसी की सफलता से खुश नहीं होते तो, आप कभी सफल नहीं हो सकते।
- ♦किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान ले कि वो तुमसे नाराज़ है कि परेशान।

शेरो-शायरी

देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से।

मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ता चला गया।

गर जिंदगी में मिल गए फिर इतिफाक से, पूछो अपना हाल तिरि बेबसी से हम।

मैं अकेला ही चला था जनिब-ए-मंज़िल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।

बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका

आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार केस में कोर्ट ने तय किए आरोप

व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे थे लालू यादव

निज संवाददाता : बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राजऊ एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं यानी अब इन लोगों के खिलाफ इस केस में मुकदमा चलेगा। राजऊ एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाले से संबंधित एक मामले में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने इस मामले में सोमवार को यह आदेश पारित किया। केंद्रीय



जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि लालू यादव, जो 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे, ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए निजी कंपनी सुजाता होटल्स को रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के पट्टे के लिए अनुचित तरीके से ठेके दिए। इतना ही नहीं इसके बदले में, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव से जुड़ी एक कंपनी को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर करोड़ों की जमीन हस्तांतरित की गई। कोर्ट ने लालू

यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी साजिश और धोखाधड़ी के कई अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव तीनों ने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो ट्रायल का सामना करेंगे। लालू फैमिली के खिलाफ जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं, उनमें आईपीसी 420, आईपीसी 120बी,

प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(डी) शामिल हैं। बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(डी) सिर्फ लालू यादव पर लगी है क्योंकि उन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने लालू यादव से पूछा क्या आप अपना अपराध मानते हैं तो लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार कर दिया। लालू फैमिली ने अदालत में कहा कि वह मुकदमे का

सामना करेंगे। वहीं राबड़ी यादव ने कहा कि ये गलत केस है। कोर्ट ने माना कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई। कोर्ट ने कहा इस मामले में आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे। लालू और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली। इस मामले में फिड प्रो को का आरोप इस स्टेज पर नजर आ रहा है। व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे थे लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव कोर्ट में पेश होने के लिए व्हील चेयर पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेमचंद गुप्ता थे। वे रविवार (12 अक्टूबर) को ही कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे। लालू और तेजस्वी यादव दिल्ली में मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर ठहरे हुए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया कि 2004 से 2014 के बीच एक साजिश के तहत पुरी और रांची में भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया और बाद में संचालन, रखरखाव के लिए बिहार की सुजाता होटल्स

प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी की गई और सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में भी बदलाव किया गया। इस चार्जशीट में आईआरसीटीसी के तत्कालीन महाप्रबंधकों वीके अस्थाना और आरके गोयल के अलावा सुजाता होटल्स के डायरेक्टर, चाणक्य होटल के मालिक विजय कोचर और वित्त कोचर का भी नाम है। गौरतलब है कि बीती 24 सितंबर को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को उक्त तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 29 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। यह मामला 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है।

वेनेजुएला की 'आयरन लेडी' मारिया कोरिना मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

निज संवाददाता : इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की 'आयरन लेडी' मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पुरस्कार से चूक गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार शुक्रवार (10 अक्टूबर) को वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया, जो फिलहाल अपने ही देश में छिपकर रह रही हैं। आयरन लेडी के नाम से भी मशहूर मचाडो का नाम टाइम पत्रिका की 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल है। इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए नोबेल समिति की अध्यक्ष ने मचाडो की शांति की एक साहसी और प्रतिबद्ध समर्थक के रूप में सराहना की, जो बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ जलाए रखती हैं। पुरस्कार की घोषणा के दौरान नोबेल समिति ने कहा कि वह वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में मचाडो के अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में एक न्यायसंगत और शांतिपूर्ण बदलाव प्राप्त करने के संघर्ष के लिए उन्हें सम्मानित करती है। मचाडो ने सुमाते नाम के



संगठन की स्थापना की, जो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करता है। जो कि मुफ्त और निष्पक्ष चुनावों की मांग करता रहा है। बता दें कि मारिया कोरिना मचाडो साल 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार थीं, लेकिन वेनेजुएला की सरकार ने उम्मीददारी रद्द कर दी। नोबेल प्राइज का ऐलान करते हुए कमेटी की तरफ से कहा गया कि हमने हमेशा से ही बहादुर लोगों का सम्मान किया है। ऐसे लोग जिन्होंने दमन के खिलाफ खड़े होकर आजादी की उम्मीद हमेशा रखी है। कमेटी ने कहा कि पिछले साल मचाडो को खुद को बचाने के लिए छिपकर रहना पड़ा था। इसके बाद भी उन्होंने

अपने देश में ही रहना चुना था। मारिया कोरिना मचाडो का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को वेनेजुएला की राजधानी कराकस में हुआ था। उन्होंने एंड्रेस बेलो कैथोलिक यूनिवर्सिटी से औद्योगिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंस्टिट्यूटो डी एस्टुडीओस सुपेरियोर्स दे एडमिनिस्ट्रसियन से बिस्त में ग्रेजुएशन किया है। शांति का नोबेल पुरस्कार हर उस शख्सियत या संस्था को दिया जाता है, जो विश्व शांति, मानवाधिकार और जंग रुकवाने के लिए अहम योगदान देते हैं। मालूम हो इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में थे, लेकिन वो इससे चूक गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 देश ट्रंप को नोबेल के लिए नामिनेट कर चुके थे, जिसमें पाकिस्तान, इस्राइल, अमेरिका, आर्मेनिया, अजरबैजान, माल्टा, कंबोडिया जैसे देशों के नाम हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अर्जेंटीना ने भी ट्रंप को शांति का नोबेल देने की सिफारिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर लंबे समय से चर्चा थी कि उन्हें यूक्रेन युद्ध और अन्य अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में मध्यस्थता के लिए नामिनेट किया जा सकता है, लेकिन नोबेल समिति ने इस साल का पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो को देने का फैसला किया।

'महिलाओं को देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए'

♦ टीएमसी सांसद सौगत राय ने की विवादित टिप्पणी

निज संवाददाता : दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में हुए सामूहिक बलात्कार पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। इसी विवाद के बीच, तृणमूल कांग्रेस के एक और नेता सौगत राय ने एक विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं को देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए और पुलिस हर ईंच सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती।

मेडिकल कॉलेज की छात्रा से बलात्कार के मामले में तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा कि घटना सामने आने के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने महिलाओं से



सतर्क रहने का आग्रह किया। सौगत ने कहा- बंगाल में ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा किसी भी अन्य राज्य से बेहतर है। हालांकि, महिलाओं को देर रात कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पुलिस हर जगह गश्त नहीं कर सकती। इससे पहले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था-वह एक निजी कॉलेज है। लड़की की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उस निजी कॉलेज की है। लड़की रात के 12:30 बजे कैपस से बाहर कैसे गई? मैंने सुना है कि

घटना जंगल इलाके में हुई थी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। पुलिस जांच कर रही है। निजी कॉलेजों को सुरक्षा कड़ी करनी चाहिए। खासकर छात्राओं की सुरक्षा कड़ी की जानी चाहिए। उन्हें रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए। पुलिस को कैसे पता चलेगा कि रात में कब और कौन बाहर जाएगा? मैं विभिन्न राज्यों के बच्चों से अनुरोध करूंगी कि वे रात में बाहर न जाएं। निजी मेडिकल कॉलेजों की भी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई रात के 12:30 बजे नहीं जाता है, तो पुलिस अब उनके घरों पर नहीं बैठेगी। ममता के इस बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। इस माहौल में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला गया।

क्यों सवालियों के घरे में रहती है संघ की विचारधारा?

दलितों और महिलाओं को संघ में सम्मान नहीं मिलने का लगता है आरोप

दिवाकर पाण्डे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल का जश्न मना रहा है। इन सौ सालों में संघ ने देश में अपनी जड़ें काफी मजबूती से जमा लीं। यह सब तब हुए जबकि कांग्रेस की सरकारों ने संघ पर प्रतिबद्ध सहित उसको लेकर जनता के बीच खूब जहर उगला था। यहां तक कि संघ की राष्ट्रभक्ति पर भी सवाल खड़े किये गये। यह भ्रम फैलाया गया कि संघ आजादी की लड़ाई के समय संघ के साथ खड़ा था। दलितों और महिलाओं को संघ में सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाया गया। कुल मिलाकर संघ ने सौ सालों में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। संघ की समाज के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता किसी से छिपी नहीं है, इसीलिए तमाम आरोपों के बाद भी संघ ने अपनी विचारधारा पर कभी समझौता नहीं किया। यह सच है कि संघ पर कई बार प्रतिबंध लगाया गया तो कांग्रेस की ही सरकारों ने समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना भी की, लेकिन संघ ने कभी भी अपने ऊपर लगे आरोपों का खुलकर खंडन नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि संघ

कभी खुलकर समाज के सामने नहीं आता है। न ही अपने किये सामाजिक कार्यों की वाहवाही बटोरता है, लेकिन संघ को सबसे अधिक विचलित तब होना पड़ता है, जब उस पर देश की आधी आबादी यानि महिलाओं की अन्तर्देखी का आरोप लगता है। संघ पर आरोप लगाया जाता है कि वह अपनी विचारधारा और संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को पुरुषों जितना सम्मान और स्थान नहीं देता। आलोचक कहते हैं कि संघ में महिलाओं को नेतृत्व भूमिका में जगह बहुत कम मिलती है। लेकिन संघ स्वयं इस धारणा का खंडन करता आया है। उसका कहना है कि महिलाओं की गरिमा और शक्ति के बिना राष्ट्र का अस्तित्व ही अधूरा है। यही कारण है कि संघ ने वर्षों से महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और संस्कार निर्माण की दिशा में कई कार्य योजनाएं चलायी हैं। संघ और उससे जुड़े संगठनों ने महिलाओं की उन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के लिये अब तक किस प्रकार के कार्य किए हैं, साथ ही किन क्षेत्रों में अभी भी और काम की आवश्यकता



महसूस की जाती है। इस पर गौर किया जाये तो देखने में यही आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं पुरुषों का संगठन है। परन्तु इसकी समानांतर शाखा महिलाओं के लिए 'राष्ट्र सेविका समिति' के रूप में कार्यरत है। यह संगठन 1936 में डॉ. हेडगेवार के सुझाव से स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना जगाना था। समिति आज देशभर में हजारों शाखाएं चला रही है। इन शाखाओं में युवतियों और महिलाओं को मानसिक व शारीरिक दृष्टि से

सशक्त बनाने की दिशा में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। दंड, योग, गीत, व्याख्यान, साहित्य अध्ययन और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं इनके नियमित आयोजन का हिस्सा हैं। इस समिति के माध्यम से अनेक महिला डॉ. हेडगेवार के सुझाव से स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना जगाना था। समिति आज देशभर में हजारों शाखाएं चला रही है। इन शाखाओं में युवतियों और महिलाओं को मानसिक व शारीरिक दृष्टि से

आलोचक कहते हैं कि यदि महिला और पुरुष समान हैं तो महिलाओं को संघ की मुख्य संरचना में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। उनका मत है कि महिला नेतृत्व को पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। संघ का पक्ष बिल्कुल भिन्न है। उसका कहना है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं और प्रकृति में भिन्नता है। इसीलिए दोनों के लिए अलग-अलग मंच बनाना ही उचित है। 'राष्ट्र सेविका समिति' इसी विचार पर संगठित है और वर्षों से दलितों रूप से कार्य कर रही है। संघ का दावा है कि समिति की महिलाएं सामाजिक उन्नति और सेवा कार्यों में कहीं अधिक सक्रिय हैं और यह विभाजन किसी बाधा के बजाय जिम्मेदारियों का दयाभाविक बंटवारा है।

स्वर्णिम भविष्य केवल शिक्षित और संस्कारित पीढ़ी के निर्माण से ही संभव है। इसी उद्देश्य से संघ की प्रेरणा से अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, जिनमें लड़कियों की संख्या उल्लेखनीय है। विद्या भारती नामक शिक्षण संगठन आज भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक नेटवर्क है। इसके विद्यालयों में बालिकाओं को संस्कारित शिक्षा प्रदान की जाती है। विज्ञान, गणित और कला जैसे विषयों के साथ नृत्य, संगीत व योग का अभ्यास भी कराया जाता है। आदिवासी बस्तियों में चलाए जा रहे 'एकल विद्यालय' योजनाओं से

बड़ी संख्या में लड़कियां शिक्षा से जुड़ी हैं। इन विद्यालयों से दूर-दराज की पहाड़ी और जनवासी बालिकाओं तक शिक्षा पहुंच रही है। छात्राओं को छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन देकर उच्च शिक्षा की ओर प्रयास करते पुर भी बल दिया जाता रहा है। संघ से जुड़े संगठनों का पढ़ाई लिखाई तक सीमित न होकर चरित्र निर्माण और राष्ट्रप्रेम से भी जुड़ी है। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनेक योजनाएं संघ व उसकी सहयोगी संस्थाएं चला रही हैं। सेवा भारती संगठन देशभर

में हजारों सेवा केंद्र चला रहा है। इनमें महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाते हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बालिकाओं के लिए पोषण आहार वितरण, आयरन की गोлияयां, स्वास्थ्य परामर्श और स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य होता है। गर्भवती महिलाओं की मदद, प्रसव के समय सहयोग, और बच्चों की देखभाल से जुड़ी योजनाओं के पीछे संघ की स्वयंसेविकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महिला जागरूकता अभियान चलाकर मासिक धर्म स्वच्छता, पोषण और परिवार स्वास्थ्य जैसे विषयों पर ज्ञान फैलाया जाता है। संघ का उद्देश्य केवल महिलाओं को शिक्षित करना भर नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। अनेक सेवा प्रकल्पों में महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प और भोजन प्रसंस्करण जैसी विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके माध्यम से महिलाएं परिवार के आर्थिक बोझ को साझा करती हैं और आत्मसम्मान के साथ समाज में योगदान देती हैं।

शेष पेज 8 पर....

मध्यप्रदेश को मुंबई से मिला ऐतिहासिक निवेश प्रस्ताव आठ ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में जल्द ही खोलेंगे अपने परिसर

तनमय जैन
भोपाल : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश अब ‘‘स्पीड ऑफ़ डूइंग बिजनेस’’ की नई परिभाषा गढ़ रहा है। मुंबई में आयोजित ‘इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपच्युनिटीज़ इन पांवर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड वाइट गुड्स इन मध्यप्रदेश’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ संवाद करते हुए निवेशकों को प्रदेश की नई औद्योगिक नीतियों, तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज़ प्रक्रिया प्रणाली से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विशेष सत्र के माध्यम से प्रदेश को ₹74,300 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें ₹19,900 करोड़ की राशि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से संबंधित है। इन प्रस्तावों से 7000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई है। निवेशकों के लिए मध्यप्रदेश बना आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए व्यवस्थाओं को सरलीकृत किया है। ‘‘ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस’’ को एक कदम आगे बढ़ाते हुए 18 नई औद्योगिक नीतियां लागू की गई हैं। इससे निवेशकों को स्पष्ट नीति, तेज़ मंजूरी प्रक्रिया और ज़मीनी सहयोग प्राप्त हो रहा



है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संभागीय स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे छोटे शहरों को भी उद्योगों में जोड़ा गया है। नर्मदापुरम का ‘मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन’ बना मुख्य आकर्षण। मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था नर्मदापुरम (मोहासा-बाबई) में स्थित भारत के पहले अत्याधुनिक ‘मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट’ के फेज़ 2 में निवेश को प्रोत्साहित करना। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि आवंटन के लिए अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2025 है, जिससे निवेशकों को एक स्पष्ट दिशा और समयबद्धता प्राप्त होती है। राणनीतिक भागीदारी की नई शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉ.

यादव ने महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब समय है कि यह सांस्कृतिक साझेदारी, औद्योगिक साझेदारी में बदले। उन्होंने कहा-महाराष्ट्र की औद्योगिक विशेषज्ञता और मध्यप्रदेश की अनंत संभावनाएं मिलकर देश को विकास की नई दिशा दे सकती हैं। यह सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि दो प्रगतिशील राज्यों के बीच नई औद्योगिक भागीदारी की शुरुआत है। वन-टू-वन मीटिंग्स और राउंडटेबल कार्यक्रम में 400 से अधिक निवेशकों और उद्योगपतियों की भागीदारी रही। साथ ही 20 से अधिक वन-टू-वन मीटिंग्स आयोजित हुईं, जिनमें टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मा,

इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी आदि क्षेत्रों के दिग्गज शामिल हुए। वहीं, दो राउंडटेबल बैठकें भी हुईं। पहली, डिप्लोमेट्स के साथ और दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण निर्माताओं के साथ। ‘‘स्पीड ऑफ़ डूइंग बिजनेस’’ बनी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने कहा-आज का निवेशक केवल ईज और कॉस्ट ऑफ़ डूइंग बिजनेस नहीं देखता, वह स्पीड भी देखता है। हम निवेश निर्णयों को इतनी तेज़ी से लागू कर रहे हैं कि यह देश में एक नया बेंचमार्क बन रहा है। उन्होंने मुंबई को सपनों का शहर बताते हुए कहा कि जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में इस शहर की लाइफलाइन हैं, वैसे ही मध्यप्रदेश की निवेशक-हितैषी नीतियां उद्योगों की ग्रोथ की लाइफलाइन बनेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन से प्रेरणा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन को प्रदेश के विकास और औद्योगिक विस्तार का मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मध्यप्रदेश हर कदम पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वहीं, मुंबई में आयोजित यह कार्यक्रम न सिर्फ निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हुआ, बल्कि मध्यप्रदेश की नीति, नीयत और नजरिए को उद्योग जगत के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने वाला मंच भी रहा।

मध्यप्रदेश में कलस्टर आधारित सब्जी उत्पादन से बढ़ल गई किसानों की तकदीर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 14 जिलों के 3000 किसान उठा रहे हैं लाभ

अजय कुमार मोहता
मध्यप्रदेश की डॉ.मोहन यादव सरकार खेती के विकास व किसानों की भलाई पर खूब जोर दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत अन्य कई योजनाएं शामिल हैं। इसी के तहत परंपरागत खेती से आय में बढ़ोतरी की राह तलाश रहे किसानों के लिए वाटरशेड विकास घटक के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 किसी बदौन से कम नहीं है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 14 जिलों के 3000 किसान अब कलस्टर आधारित सब्जी उत्पादन से जुड़कर ₹40 से 50 हजार तक की आय अर्जित कर रहे हैं। यह पहल न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सशक्त बना रही है, बल्कि गांवों में ग्रामीण आजीविका को भी नई दिशा दे रही है। रतलाम जिले के नौगांवाकला के किसान तेजपाल की मिसाल ले सकते हैं। बड़ी बात यह कि उनके जैसे किसान जो पहले सिर्फ खाने लायक सब्जी उगाते थे, अब आधा एकड़ में टमाटर और मिर्च की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। यह बदलाव



संभव हुआ है वाटरशेड विकास घटक की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के नवाचार से जिसने पहली बार जल संरक्षण को आजीविका से जोड़ा है।

100 से 150 किसानों का चयन किया गया योजना के तहत प्रत्येक परियोजना में सिंचाई की सुविधा वाले 100 से 150 किसानों का चयन किया गया। इन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए 835 लीड वैजिटेबल फार्मर चिन्हित किए गए और उन्हें मास्टर ट्रेनर बनाकर गांवों में सब्जी उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धति सिखाई गई। सरकार किसानों को प्रति किसान ₹30 हजार तक का अनुदान भी दे रही है, जिससे वे खाद,

दवाइयों और अन्य संसाधनों की खरीद कर सकें। इतना ही नहीं 50 से 60 किसानों के बीच गांव में ही शेड नेट नर्सरी तैयार की जा रही है, जिससे उन्नत किस्म की पौध समय पर उपलब्ध हो सके। इन नर्सरियों के लिए ₹1.30 लाख तक की सहायता भी दी जा रही है। अगले सीजन में और 9000 किसान होंगे लाभान्वित। इस योजना की सफलता को देखते हुए रबी सीजन में 36 जिलों की 85 परियोजनाओं में विस्तार किया जा रहा है, जिससे लगभग 9000 और किसान लाभान्वित होंगे। वर्तमान में धार, रतलाम, खरगोन, बड़वानी, सागर, गुना, इंदौर, श्योपुर सहित 14 जिलों में इसका सफल संचालन हो रहा है। तकनीक और योजना पर आधारित खेती के सहारे किसान बढ़ रहे समृद्धि की ओर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की इस पहल से साफ है कि अब किसान सिर्फ मौसम पर नहीं बल्कि तकनीक और योजना पर आधारित खेती से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों को साधने की तैयारी में कांग्रेस

निज संवाददाता : बिहार के चुनावी मौसम में इस बार हवा कुछ अलग बह रही है। जहां एक तरफ विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की बातें जोर पकड़ रही हैं, वहीं रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता उछालने की घटना अब बिहार विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी इन घटनाओं को हाथों-हाथ लेकर दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर्स को साधने की पूरी तैयारी में जुट गई है। पार्टी के नेता कहते हैं कि ये सिर्फ दो घटनाएं नहीं, बल्कि भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर हो रहे अत्याचारों का जीता-जागता सबूत हैं।

सबसे पहले बात करते हैं रायबरेली की उस दर्दनाक घटना की, जो पूरे देश को झकझोर रही है। 2 अक्टूबर 2025 को रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में 38 साल के दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को गांव वालों ने चोरी के शक में इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान चली गई। हरिओम अपनी ससुराल ईश्वरदासपुर आया था, लेकिन गांव वालों ने उसे झूठे चोर समझ लिया। दो घंटे तक लाठी-डंडों, बेल्ट और लात-घुंत्तों से पीटाई होती रही। हरिओम कराहते हुए बार-बार राहुल गांधी-राहुल गांधी का नाम ले रहा था, मानो मदद की गुहार लगा रहा हो। हैरानी की बात यह है कि पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हरिओम को अस्पताल ले जाने की बजाय गांव वालों के हवाले छोड़ दिया। हरिओम की पत्नी का कहना है कि पुलिस ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। किसी ने इस पूरी घटना के तीन वीडियो बना लिए, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। वीडियो में हरिओम की चीखें और उसकी आखिरी सांसें साफ सुनाई दे रही हैं, जो किसी भी इंसान का कलेजा चीर सकती हैं। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन परिवार का आरोप है कि असली दोषी अब भी आजाद घूम रहे हैं। हरिओम के पिता गंगादीन ने बताया कि उनका बेटा मजदूरी करता था और परिवार की कमाई टूट गई है।



इस घटना ने एक बार फिर मांब लिचिंग के पुराने घावों को कुरेद दिया है, जहां दलित और कमजोर वर्ग के लोग आसानी से निशाना बन जाते हैं। कांग्रेस ने इसे समाज पर कलंक बताया और भाजपा सरकार पर सवाल उठाए कि क्या यूपी में जंगलराज चल रहा है? वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी नेता राहुल गांधी ने तुरंत हरिओम के परिवार से फोन पर बात की। उन्होंने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया और अपने एकसिंह डल पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। राहुल ने लिखा, रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं- इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है।

आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीब- हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी आवाज कमजोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है और जिसकी जिंदगी सस्ती समझी जाती है। देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र का भरोसा दिलाया जा रहा है, जबकि संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है और ईसाफ की जगह डर ने। मैं हरिओम के परिवार के साथ खड़ा हूं- उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। भारत का भविष्य समानता और

मानवता पर टिका है और यह देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं। राहुल की यह पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है और दलित समुदाय में काफी सराही जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जो खुद दलित समुदाय से हैं, ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मांब लिचिंग और बुलडोजर अन्याय आज की भयावह हकीकत बन गए हैं। खरगे और राहुल ने संयुक्त बयान में इसे संविधान के खिलाफ अपराध बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार से मिलकर सरकार से नौकरी और मुआवजे की मांग की। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और राजेंद्र गौतम जैसे नेता भी परिवार से मिले और बोले कि भाजपा में दलितों का उन्मीड़न हो रहा है। यह घटना फतेहपुर के दलित समाज में आक्रोश पैदा कर रही है, जहां हरिओम को राहुल का नाम लेने पर और पीटा गया। इस घटना के ठीक बाद, 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक और कुदृष्ट घटना वाली वारदात हुई। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जो खुद दलित समुदाय से आते हैं, पर 71 साल के वकील राकेश किशोर ने जूता उछाल दिया। राकेश बरेली का रहने वाला है और खुद को सनातन धर्म का रक्षक

‘बांग्लादेश के मदरसों में सिखाई जाती है संस्थागत रूप से हिंदू-घृणा’ तस्लीमा ने फिख इस्लामी शिक्षा पर साधा निशाना

निज संवाददाता : उनका धर्म इस्लाम है। लेकिन वे हमेशा से धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ रही हैं। इसीलिए प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरिन को उनके वतन से निकाल दिया गया था। वे वर्तमान में विदेश में रह रही हैं। उन्होंने अपनी लेखनी में एक विरोधात्मक रूख बनाए रखा है। वे अक्सर सोशल मीडिया पर विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करती हैं। इन पर विवादों की कोई कमी नहीं है। बेशक, तस्लीमा इससे डरती नहीं हैं। इस बार, उन्होंने बांग्लादेश के मदरसों में शिक्षा की स्थिति पर एक रील साझा की, जिसकी कड़ी आलोचना हो रही है।

लेखिका का दावा है कि बांग्लादेश के मदरसों में हिंसा, घृणा और सांप्रदायिकता संस्थागत रूप से सिखाई जाती है। तस्लीमा द्वारा फेसबुक पर साझा की गई रील में एक मदरसे में बच्चों की एक कक्षा दिखाई गई है। अगर यह विषय हिंदू त्योहार में शामिल किया जाता है, तो इससे मुसलमानों को क्या नुकसान होता है? रील में, शिक्षक यह



कहते हुए सुनाई देते हैं-अगर आप हिंदू पूजा में जाते हैं, तो इस्लाम कमजोर हो जाता है। छोटे लड़के इस शब्द को बार-बार दोहरा रहे हैं। इस तरह का पाठ निस्संदेह तीव्र हिंदू विरोध का संकेत है।

तस्लीमा ने यही कहा। रील शेयर करते हुए उन्होंने लिखा-बांग्लादेश के मदरसों में संस्थागत रूप से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, घृणा, असम्पत्ता, बर्बरता और सांप्रदायिकता सिखाई जाती है। इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की गई है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में इस्लामी

चरमपंथ का उदय काफी स्पष्ट हो गया है। हिंदू उत्पीड़न बढ़ गया है। वहां के अल्पसंख्यक हर पल डर में रहते हैं। यूनुस की अंतरिम सरकार को इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यूनुस खुद दावा करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हो रही है। लेकिन, वहां के मदरसे में पढ़ाई का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उससे पता चलता है कि बच्चों का हिंदू धर्म के विरोध में ब्रेनवॉश किया जा रहा है।

इसीलिए उन्हें सिखाया जा रहा है-अगर आप हिंदुओं की पूजा करते हैं, तो इस्लाम कमजोर हो जाता है। असली शिक्षा आपको उदार होना सिखाती है, मानवता सिखाती है। यह धर्म के अंधेरे पक्ष को दूर करती है और उसे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करती है। लेकिन बांग्लादेश के मदरसों में ठीक इसके उलट तस्वीर देखने को मिलती है। इसलिए तस्लीमा नसरिन द्वारा ऐसी शिक्षा की निंदा स्वाभाविक है।

और ठेकों में इंबीसी आरक्षण का दांव चला, जो बिहार के पिछड़ों को लुभा रहा है। कांग्रेस महागठबंधन में 55 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है, जहां राजद के साथ सीट बंटवारे पर मुहर लग चुकी है। पार्टी सीमांचल इलाके पर फोकस कर रही है, जहां मुस्लिम और दलित वोटर ज्यादा हैं। बिहार में दलित वोटर्स का इतिहास देखें तो वे कभी एकमुश्त किसी पार्टी को नहीं जाते। रविदास और पासवान जातियां प्रमुख हैं। एनडीए में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान खुद को दलितों का हितैषी बताते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भाजपा-जदयू सरकार में दलित अत्याचार बढ़े हैं।

चुनाव आयोग पर भी आरोप लग रहे हैं कि वोटर लिस्ट में फर्जीबाड़ा हो रहा है। कई जगह जिंदा दलितों को मृत दिखाया गया है, जबकि मृतकों को जिंदा। कांग्रेस का दावा है कि यह गरीब-दलितों के वोट चुराने की साजिश है। राहुल की वोटर अधिकांश यात्रा ने 23 जिलों में वोट चोरी को मुद्दा बनाया। विपक्षी पार्टियां जैसे राजद और सीपीआईएमएल भी दलितों पर फोकस कर रही हैं। सीपीआईएमएल के दीपान्वर भट्टाचार्य कहते हैं कि बिहार में दलित बस्तियों में आग लगाकर बेदखली हो रही है, मजदूरों के हाथ काटे जा रहे हैं। पिछले 20 साल की सरकार में बरेलीगारी और पलायन चरम पर है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी नए विकल्प के रूप में उभर रही है, लेकिन राहुल और तेजस्वी का भरोसा दलितों को अपनी ओर खींच रहा है। ये मुद्दे चुनाव को नया मोड़ दे सकते हैं। जहां भाजपा विकास और मोदी-योगी की छवि पर जोर दे रही है, वहीं कांग्रेस दलितों की भावनाओं को भुनाने की कोशिश में है। रायबरेली और सीजेआई घटना ने दलितों में गुस्सा भरा है, जो बिहार में वोट बन सकता है। अगर कांग्रेस सफर हुई, तो यह न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। अंत में, सवाल यही है-क्या संविधान और न्याय की लड़ाई चुनावी जीत दिलाएगी या विकास की बातें हावी रहेंगी? बिहार के मतदाता ही फैसला करेंगे।

राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेंगे टोटो

आसनसोल। बेतरतीब ढंग से बग़ाय़ के शहरों और कसबों में चल रहे टोटो की संख्या को नियंत्रित करने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। 30 नवंबर के बाद राज्य में वही टोटो सड़कों पर दिखेंगे जिनके पास टेम्पेरी टोटो एनरोलमेंट नंबर (टीटीईएन) होगा। शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने उक्त जानकारी दी। उनके साथ परिवहन सचिव डॉ सौमित्र मोहन एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। कसबा स्थित परिवहन विभाग दो में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अक्टूबर को राज्य भर में एक साथ टोटो का पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। जो 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान टोटो मालिकों को



पंजीकरण के लिए परिवहन विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। श्री चक्रवर्ती ने बताया कि पंजीकरण शुल्क 1000 रुपया जमा करना होगा। पंजीकरण की अवधि के छह महीने बाद 100

रुपये प्रति माह, यानी 12 महीनों में 1200 रुपये चार्ज लगेगा। उन्होंने बताया कि टीटीईएन वाले टोटो को बीमा कवर के दायरे में भी लाया जायेगा। सूत्रों के मुताबिक, सभी टोटो नंबर मिलने के बाद, परिवहन विभाग की योजना है कि

जिन जिलों या शहरों में टोटो की संख्या ज्यादा होगी, वहां ऑड और ईवन नंबर के आधार पर हर दूसरे दिन सड़कों पर चलाया जाये। यानी अलग-अलग दिनों में अलग अलग टोटो चलेंगे। इस नियम को जनवरी 2026 से लागू

करने की योजना है। हालांकि यह पूरा काम संबंधित नगर निगम और नगरपालिका और स्थानीय पुलिस थाने की निगरानी में होगा। जानकारी के अनुसार टीटीईएन पंजीकरण फिलहाल, अस्थायी नामांकन संख्या होगी। नंबर प्लेट पर एक क्यूआर कोड होगा। राज्य के सभी टोटो इसी अस्थायी नामांकन संख्या के साथ पंजीकरण के दायरे में आयेंगे। इनकी पूरी सूची संबंधित आरटीओ कार्यालय में होगी। वर्तमान में राज्य में कितने टोटो चल रहे रहे हैं, इसका आंकड़ा राज्य सरकार के पास नहीं है। मंत्री ने स्वीकार करते हैं कि टोटो की बेलेगाम संख्या से यातायात जाम का कारण बन रही है और परेशानी का कारण बन रही है, फिर भी टोटो को बंद नहीं किया जा सकता। परिवहन विभाग इसे नियंत्रित कर के चलाते जा रहा है।

विधायिका अग्निमित्रा ने ईडी छापों को लेकर तृणमूल पर बोला तीखा हमला

आसनसोल: भाजपा विधायक और पार्टी की राज्य महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने शुक्रवार को हाल ही में ईडी छापों, राज्य पहचान रजिस्टर (एसआईआर) से जुड़े विवाद और मुख्य चुनाव अधिकारी पर लगे आरोपों को लेकर तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला।मंत्री सुजीत बोस के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे का जिक्र करते हुए अग्निमित्रा ने कहा, जब ईडी तृणमूल के एक मंत्री के घर पर छापेमारी कर रही है, तो मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं लगती। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है जो छापेमारी करने से पहले मेरी अनुमति नहीं लेती।इस घटनाक्रम को आश्चर्यजनक बताते हुए, उन्होंने आगे कहा, यह चौंकाने वाला है कि तृणमूल के एक मंत्री के घर पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। सुजीत बोस, ज्योतिर्मय मलिक, पार्थ चटर्जी और अभिषेक बनर्जी



की 2011 से पहले की संपत्तियों की देखिए - और अब भी देखिए। पिछले चौदह सालों में उनकी संपत्ति इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? जनता को यह जानने का हक है कि इतनी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए वे किस तरह का धंधा या व्यापार करते हैं। उन्होंने बंगाल की जनता को लुटा है और करोड़ों की संपत्ति बनाई है। जो लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, उन्हें छापे का सामना करना पड़ेगा - चाहे वे शीर्ष नेता ही क्यों न हों।अग्निमित्रा ने

तृणमूल नेतृत्व पर जनता को लुटकर और सत्ता का दुरुपयोग करके अकूत संपत्ति इकट्ठा करनेर का आरोप लगाया और कहा कि वे जाँच एजेंसियों के सामने जवाबदेही से बच नहीं सकते।'ममता बनर्जी सिर्फ धमकाना जानती हैं': एसआईआर पर टिप्पणी पर अग्निमित्रा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में दावा किया था कि बंगाल में एसआईआर लागू करने से दौरे हो सकते हैं।

पत्नी की हत्या कर, पति ने थाने में किया आत्मसमर्पण

दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या करने के बाद खुद थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी पति पेशे से ट्यूशन टीचर (गृहशिक्षक) हैं। पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया।यह सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना शुक्रवार शाम को दुर्गापुर के धोबी घाट इलाके में हुई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम दुर्गा दास कर है, जो पेशे से गृहशिक्षक है। मृतका की पहचान उसकी पत्नी मुकुल कर के रूप में हुई है।धोबी घाट इलाके के स्थानीय निवासियों ने बताया कि मुकुल कर को हमेशा हँसमुख देखा जाता था। लेकिन शुक्रवार शाम होते ही इलाके का माहौल बदल गया। अचानक क्षेत्र में

पुलिस पहुँची और भीड़ जमा हो गई। तभी पता चला कि दुर्गा दास कर ने अपनी पत्नी मुकुल कर की हत्या कर दी है और हत्या के बाद स्वयं थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया है।स्थानीय निवासियों का दावा है कि घर की मालकिन की हत्या किसी धारदार हथियार या कटारी से की गई है। आत्मसमर्पण की सूचना मिलते ही दुर्गापुर पुलिस मौके पर पहुँची और मृतका के शव को बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर उप-मंडल अस्पताल भेज दिया गया है।दुर्गापुर थाना पुलिस ने हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच शुरू कर दी है और गिरफ्तार किए गए पति दुर्गा दास कर से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है।

बाहरी तत्वों का स्कूल-चर्च पर कब्जा करने की साजिश ?

आसनसोल: आसनसोल स्थित एजी चर्च स्कूलों के प्रबंधन को लेकर चल रहे विवादों के बीच, द एसंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल की प्राचार्या जैसिका स्पेंसर ने शनिवार शाम एक बड़ा बयान दिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी तत्व स्कूल और चर्च को कब्जा कर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस संस्था का स्कूलों पर कोई अधिकार नहीं है। प्राचार्या स्पेंसर ने स्पष्ट किया कि संबंधित संस्था का कार्य केवल धार्मिक सलाह देना है। उन्होंने कहा, लेकिन वह लोग गलत तरीके से कुछ लोगों की मिलीभगत से साजिश कर रहे हैं। जबकि ऐसा करने का उनका कोई अधिकार नहीं है।इन्होंने



समाज में गलत तरह के संदेश से धर्म फैलाने का आरोप भी लगाया। प्राचार्या ने जोर देकर कहा कि स्कूल का संचालन पूरी तरह से एक पंजीकृत सोसाइटी के अधीन है, जो कि एक स्वायत्त

संस्था है और इसके अपने नियम-कानून हैं।उन्होंने बताया, स्कूल के कर्मचारियों एवं प्रबंधन अधिकारियों आदि का वेतन भुगतान सबकुछ सोसाइटी के माध्यम से होता है। उनके

अनुसार, एजीएनआई केवल उन्हें धार्मिक सलाह दे सकता है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि हमारे स्कूलों के संचालन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सोसाइटी के अधीन आसनसोल, रानीगंज, उखड़ा, सोदपुर जैसे स्कूल आते हैं, जहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं।प्राचार्या ने चिंता व्यक्त की कि अगर स्कूल में कोई गड़बड़ी पैदा होती है, तो उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। उन्होंने अपील की कि स्कूल के संचालन में किसी तरह की बाधा या गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए।इस संबंध में एजीएनआई पदाधिकारियों से संपर्क न हो पाने के कारण उनका पक्ष नहीं मिल सका है।

रानीगंज मास्टर प्लान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक



आसनसोल : पश्चिम बर्धमान जिला मजिस्ट्रेट एस. पोन्बलम की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में रानीगंज मास्टर प्लान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में कानून मंत्री मलय घटक, रानीगंज विधायक तापस बनर्जी, जमुरिया विधायक हरे राम सिंह, पांडेश्वर

विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) के चेयरमैन कवि दत्ता सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि रानीगंज के धसान प्रभावित इलाकों के निवासियों के

पुनर्वास पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अंडाल क्षेत्र के दक्षिण खंड में 4,000 प्लेट तैयार हैं। पुनर्वास के लिए नई नीति तैयार की गई है, जिसे उद्योग विभाग को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। अनुमोदन मिलते ही कार्यवाही शुरू हो जाएगी। जमुरिया के तैयार प्लेटों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने के कारण विलंब हो रहा था, लेकिन हाउसिंग विभाग से आज ही सूचना मिली है कि प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और पुनर्वास जल्द शुरू होगा। जमुरिया विधायक हरे राम सिंह ने भी कहा कि बैठक में सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पर जोर दिया गया। जो भूमि अधिग्रहण, फंडिंग एवं पुनर्वास पैकेज पर केंद्रित रहेगी।



दुर्गापुर। दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ हुए सनसनीखेज दुष्कर्म कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार, इन व्यक्तियों से लगातार पूछताछ की जा रही है।जांच में ड्रोन और फॉरेंसिक टीम घटना की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही है।पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ड्रोन कैमरे की मदद से

पूरे घटनास्थल और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। इसके साथ ही, फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक नमूने और सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने आशवासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर कुछ अन्य व्यक्तियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।सियासी दबाव और पीड़िता की स्थितिइस घिनौनी वारदात ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। प्रशासनिक जांच के साथ-साथ राजनीतिक गलियारों में भी तनाव और चर्चा का माहौल है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ दल पर हमलावर है।इस बीच, डॉक्टर सूत्रों से खबर मिली है कि पीड़िता फिलहाल स्वस्थ है और उसका इलाज चल रहा है।

टीएमसी नेताओं ने साढ़े 14 साल में अवैध तरीके से संपत्ति बनाई : अग्निमित्रा पाल

आसनसोल : आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से बीमार चल रही थी आज वह फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची अपने विधायक को अपने बीच पाकर कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था उन्होंने विधायक के समर्थन में नारे लगाए रानीगंज के रानी साएर मोड़ इलाके में विधायक का भव्य स्वागत किया गया इसके उपरांत भाजपा समर्थकों ने एक बाइक रैली में निकली जो काली पहाड़ी जुबली होते हुए बर्नपुर के बारी मैदान काली मंदिर पहुंची। यहां पर विधायक ने काली मंदिर में पूजा अर्चना की इसके बाद टीएमसी के कुछ नेताओं के घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा छापा मारने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में अग्निमित्रा



पिछले 1 महीने से वह बीमार चल रही थी लेकिन आज फिर से अपने समर्थकों के बीच जाकर वह बहुत खुश हैं और समर्थकों ने उनका जिस तरह से स्वागत किया इसे देखकर उनकी आंखें नम हो गईं । वही आज फिर टीएमसी के कुछ नेताओं के घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा छापा मारने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में अग्निमित्रा

पाल ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने अपने साढ़े 14 साल के कार्यकाल के दौरान अवैध तरीके से संपत्ति बनाई है इसका जवाब उनका जांच एजेंसी को देना होगा इसका जवाब उन्हें बंगाल की जनता को देना होगा इसलिए वह इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहते लेकिन अगर कहीं पर कुछ गलत हुआ है तो जांच एजेंसी इसकी जांच जरूर करेगी

ईसीएल ने सशक्तिकरण और शिक्षा पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया

आसनसोल: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) ने सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएँ (डब्ल्यू आईजीएस) के बैनर तले पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाकर एक मील का पथर स्थापित किया। 10 से 11 अक्टूबर तक आयोजित इस दो दिवसीय समारोह का विषय था उसे सशक्त बनाएँ, उसे शिक्षित करें, उसका उत्सव मनाएँ, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति ईसीएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।उद्घाटन समारोह में ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री सतीश झा, निदेशक (वित्त) मोहम्मद अंजार आलम और निदेशक (तकनीकी/योजना एवं



परियोजना) श्री गिरिश गोपीनाथन नायर भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति ने समावेशिता, शिक्षा और समग्र विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों के प्रति संगठन की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाया।आस-

पास के स्कूलों की लगभग 50 से 60 छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें विभिन्न इंटरैक्टिव और शैक्षिक गतिविधियाँ शामिल थीं। इस दिन का एक प्रमुख आकर्षण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर

एक जागरूकता सत्र था, जिसमें स्त्री रोग संबंधी कैंसर, मासिक धर्म स्वच्छता और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया - जिसका उद्देश्य युवा लड़कियों में स्वास्थ्य साक्षरता और आत्मविश्वास बढ़ाना था। इस अवसर पर बोलते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों ने लड़कियों के लिए सीखने, नेतृत्व करने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के अवसर पैदा करने के महत्व पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में ईसीएल द्वारा अपनी सामाजिक पहुँच को मजबूत करने और अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के विरोध में भाजपा का विरोध प्रदर्शन

आसनसोल: दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के विरोध में भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा त्रिवेणी मोड़ पर शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध फैल गया।प्रदर्शनकारियों ने सड़क सीखने, नेतृत्व करने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के अवसर पैदा करने के महत्व पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में ईसीएल द्वारा अपनी सामाजिक पहुँच को मजबूत करने और अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।



की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ओडिशा की एक युवती जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने दुर्गापुर आई थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। वह कल रात खाना खरीदने के लिए बाहर गई थी जब यह घटना

घटी। बंगाल में यह पहला ऐसा मामला नहीं है - ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके पास गृह विभाग भी है, की तीखी आलोचना की और उन पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई नहीं करतीं। आरोपियों पर हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है और उन्हें जल्द ही राहत मिल जाती है।महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए, पॉल ने कहा, रपत्रक बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम ओडिशा से बंगाल में पढ़ाई करने आई एक लड़की की सुरक्षा नहीं कर सके। त्योहारों और समारोहों पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन असली देवी - हमारी महिलाएं - यहाँ असुरक्षित रहती हैं।किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए धरना स्थल पर पुलिस तैनात की गई थी। आंदोलन समाप्त होने के बाद यातायात बहाल हो गया।

मोहन सरकार की भावांतर योजना से लौटी सोयाबीन किसानों की मुस्कान

हर्षवर्धन पांडे
सोयाबीन मध्यप्रदेश के किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार है। यहां बाजार मूल्यों की अस्थिरता किसानों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन सरकार ने किसानों को भावांतर योजना के माध्यम से बड़ी राहत प्रदान की है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और बाजार मूल्य के अंतर की भरपाई करेगी। यह योजना किसानों को बाजार जोखिम से बचाने का एक प्रभावी उपकरण साबित होगी। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादकों के लिए इस योजना को पुनः लागू करने की घोषणा की है जो मध्यप्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी राहत का संकेत है।

2025 में सोयाबीन की कीमतों में गिरावट के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भावंतर योजना की घोषणा करके किसानों के हित में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस बड़ी घोषणा से राज्य के 50 लाख हेक्टेयर सोयाबीन क्षेत्र और 25 लाख से अधिक छोटे-मझोले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत अधिसूचित तिलहनी फसल के लिए भावांतर योजना वर्ष 2018-19 से लागू की गई है। भारत सरकार ने घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा राज्य के मंडी के मांडल भाव/विक्रय मूल्य अंतर की राशि कृषकों को दिलवाने का प्रावधान किया है। किसान पहले की तरह अपनी उपज मंडियों में बेचेंगे। एमएसपी और मंडी का मांडल भाव/विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि का किसान को डीबीटी से

योजना से राज्य के 50 लाख हेक्टेयर सोयाबीन क्षेत्र और 25 लाख से अधिक छोटे-मझोले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी



भुगतान किया जायेगा। इसके लिए किसान द्वारा ई-पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए किसान का उत्पादन मांडल भाव 4600 रूपए पर हुआ है तो समर्थन मूल्य 5328 में से शेष अर्थात भावांतर राशि 628 रूपए प्रति किंटल राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। किसान को समर्थन मूल्य बराबर ही राशि प्राप्त होगी। यदि किसान की उपज का विक्रय मूल्य एमएसपी से कम है परंतु राज्य के औसत मांडल प्राइज के समतुल्य है ऐसी स्थिति में भी किसान को एमएसपी और बिक्री मूल्य के भावांतर की राशि प्रदान की जाएगी। तीसरी स्थिति में कृषि उपज का विक्रय मूल्य राज्य के औसत मांडल प्राइस से कम होने की दिशा में किसान को एमएसपी और घोषित औसत मांडल प्राइस के भावांतर की राशि प्रदान की जाएगी।

प्रत्येक स्थिति में किसान का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। मध्यप्रदेश में सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। मोहन सरकार के इस निर्णय से सोयाबीन उत्पादक के किसानों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के बीच के अंतर की राशि सरकार देगी। पंजीयन के बाद भावांतर योजना में सोयाबीन का विक्रय किया जा सकेगा। राशि फसल विक्रय के 15 दिवस के अंतर किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। भावांतर योजना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मध्यप्रदेश में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन का कार्य 3 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। पंजीयन के बाद भावांतर योजना में सोयाबीन का

विक्रय 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक किया जा सकेगा। पंजीकृत कृषक और उनके रकबे के सत्यापन की प्रक्रिया राजस्व विभाग के माध्यम से पूर्ण होगी। किसानों के भावांतर की राशि फसल विक्रय के 15 दिवस के भीतर उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसान मंडियों में पहले की तरह ही सोयाबीन का विक्रय करेंगे। यदि फसल एमएसपी से कम भाव पर बिकती है तो सरकार अंतर की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करेगी। इसके लिए किसानों को योजना में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि मंडी में सोयाबीन का भाव एमएसपी से कम लेकिन राज्य सरकार के घोषित औसत मांडल भाव से अधिक है तो एमएसपी और वास्तविक बिक्री मूल्य का

अंतर सरकार देगी। यदि मंडी भाव औसत मांडल भाव से भी कम है तो एमएसपी और मांडल भाव का अंतर किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा है कि योजना को पारदर्शी ढंग से लागू किया जाए और किसानों तक पूरी जानकारी पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार ने किसानों की समग्र कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में दशहरा के अवसर पर 8.84 लाख किसानों के खातों में 653.34 करोड़ रुपये की राहत राशि ट्रांसफर की गई जो अतिवृष्टि, बाढ़, कीट व्याधि और सोयाबीन में पीला मोजेक रोग से प्रभावित फसलों के लिए थी। इस बार प्रदेश के 13 जिलों के 4.94 लाख किसानों को पहली बार इस रोग के लिए विशेष सहायता मिली।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों के हित के लिए सरकार के पास राशि की कोई कमी नहीं है। किसान-कल्याण मोहन सरकार की पहली प्राथमिकता है। किसानों के लिए राज्य सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। जिस तरह धान और गेहूं पर किसानों को उनके परिश्रम की कीमत दिलवाने का कार्य किया गया उसी तरह प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को भी लाभ सरकार द्वारा दिलाया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिलवाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध नजर आती है।

मध्यप्रदेश की भावांतर योजना किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने का मोहन सरकार का एक बहुत ही साहसिक प्रयास है। इस योजना के माध्यम से सोयाबीन पर केंद्रित लाखों किसानों को एक तरफ जहाँ बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी वहीं इससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए भावांतर योजना के प्रति किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। किसानों को अब किसी प्रकार का कोई नुकसान सरकार द्वारा नहीं होने दिया जायेगा। केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 5328 प्रति किंटल तय किया गया है लेकिन बाजार में कई बार किसानों को इससे कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही थी। ऐसे में मोहन सरकार की यह भावांतर योजना सोयाबीन किसानों को निश्चित तौर पर बड़ी राहत देने का काम करेगी।

अजब-गजब

2026 के लिए बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणियां

होगा तीसरा महायुद्ध, एलियन का हमला और एआई का राज

निज संवाददाता : बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां 2026 को लेकर फिर चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि आने वाला साल मानव सभ्यता के लिए निर्णायक मोड़ हो सकता है, जब युद्ध, एआई और आसमान से आने वाले अनजान प्राणी सब कुछ बदल देंगे। लेकिन क्या यह सब सिर्फ मिथक हैं या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार, 2026 में विश्व में ऐसा भू-राजनीतिक और प्राकृतिक संकट जन्म ले सकता है जो अब तक की सभ्यता को हिला देगा। उनकी कथित भविष्यवाणियों में कहा गया है कि पूर्वी क्षेत्र से एक ऐसा युद्ध शुरू होगा जो धीरे-धीरे पूरे पश्चिम तक फैल जाएगा। कई जानकार इस दावे को तीसरा विश्व युद्ध बता रहे हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के



अनुसार एआई 2026 में इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वह मानव जीवन के फैसलों में हावी हो जाएगी। यह वही समय होगा जब एआई मानव नौकरियों और

शासन-प्रणाली पर सीधा प्रभाव डालना शुरू करेगा यानी मशीनों का शासन युग का आरंभ होगा। कई यूरोपीय मीडिया स्रोतों के अनुसार, बाबा वेंगा ने 2026 में भयंकर प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी दी थी जैसे विशाल भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और मौसमीय उलटफेर, जिससे पृथ्वी की करीब 7-8 प्रतिशत जमीन प्रभावित हो सकती है। यानी एक ऐसा वर्ष जब प्रकृति खुद इंसान से हिसाब मांगेगी। बाबा वेंगा की 2026 को लेकर एक और रहस्यमय भविष्यवाणी है। इनके अनुसार मानव सभ्यता का पहली बार बाहरी जीवन (एलियन लाइफ) से संपर्क होगा। नवंबर 2026 में एक बड़ा अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है। यानी हम अकेले नहीं हैं यह सत्य दुनिया के सामने आ सकता है।

10,000 साल पहले चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया में शुरू हुआ था ममी बनाने का खेल



परिजनों के प्रति प्यार जताने के लिए लोग शव को आग और धुएं में सुखाते थे

जब भी ममी का नाम आता है, हमारे दिमाग में मिस्र की तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगती है। ताजा रिसर्च से पता चला है कि ममी बनाने का असली खेल तो 10,000 साल पहले चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया में शुरू हुआ था। यहां लोग अपने मृतकों को बचाने के लिए उन्हें आग और धुएं से सुखाते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन, थाईलैंड, लाओस, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया में पुरानी कब्रें खोदकर देखी गईं। वहां मिले कंकाल किसी बच्चे की तरह गोल-गोल सिकुड़े हुए थे। शुरुआत में ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन जांच से पता चला है कि दफनाने से पहले शवों को आग और धुएं पर लंबे समय तक रखा गया। इसी प्रक्रिया से उनकी देह जल्दी गलती नहीं थी। रिसर्च में कहा गया कि ऐस-ने और खास टेक्निक से हड्डियों की जांच की गई। नतीजा यह निकला कि हड्डियों पर हल्की गर्मी और कालिख के निशान थे, लेकिन जलने का कोई सबूत नहीं मिला। यानी ये शव धीरे-धीरे धुएं में सुखाए गए

थे, जलाए नहीं गए। इसे ही वैज्ञानिकों ने 'स्मोक्ड ममी' का नाम दिया। यह तरीका सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। इंडोनेशिया के पापुआ में दानी और पुमो समुदाय आज भी अपने पूर्वजों को ऐसे ही ममी बनाकर रखते हैं। ये प्यार, याद और भक्ति का एक तरीका है। वे जानते हैं कि दफनाने से पहले शवों को आग और धुएं पर लंबे समय तक रखा गया। इसी प्रक्रिया से उनकी देह जल्दी गलती नहीं थी। रिसर्च में कहा गया कि ऐस-ने और खास टेक्निक से हड्डियों की जांच की गई। नतीजा यह निकला कि हड्डियों पर हल्की गर्मी और कालिख के निशान थे, लेकिन जलने का कोई सबूत नहीं मिला। यानी ये शव धीरे-धीरे धुएं में सुखाए गए

दुनिया की सबसे भारी सोने की ड्रेस



कीमत 11 करोड़

सऊदी अरब की अल रोमाइजन गोल्ड एंड ज्वेलरी कंपनी ने 10 किलो सोने से एक ड्रेस तैयार की है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये दुनिया की सबसे भारी सोने की ड्रेस है और इसी वजह से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। इस ड्रेस को 'दुबई ड्रेस' का नाम दिया गया है और यह अभी शारजाह वॉच एंड ज्वेलरी एक्सपोजे में दिखाई गई है। इस ड्रेस को शुद्ध 21 कैरेट सोने से तैयार किया गया है और इसका वजन 10.0812 किलोग्राम है। इसकी कीमत की अगर बात करें तो यह 4.6 मिलियन एडईटी (लगभग 11 करोड़ रुपये) है। दुबई ड्रेस में चार मुख्य चीजें हैं जिसमें 398 ग्राम का सोने का मुकुट, 8,810.60 ग्राम का हार, 134.1 ग्राम के ईयररिंग्स और 738.5 ग्राम का 'हियर' पीस शामिल हैं। इसमें रंगीन कीमती पत्थरों से जड़े जटिल डिजाइन और बारीक नकाशी है, जो इसे एक कलात्मक कृति बनाती है। यह सोने और गहनों की भाषा में अमीराती सांस्कृतिक विरासत की कहानी बयां करती है। गहने की कंपनी ने कहा कि उनके डिजाइनरों ने "दुबई ड्रेस" के लिए असली अमीराती विरासत से प्रेरणा ली है। यह पीस इतिहास की झलक और अमीराती सभ्यता की शुद्धता को आधुनिक टच के साथ दिखाता है। मीडिया न्यूज के अनुसार अल रोमाइजन गोल्ड के रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन अल धैबानी ने बताया कि यह काम यूएई की ग्लोबल लीडरशिप हासिल करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है और दुबई को सोने और गहनों के शोकीनों के लिए सबसे अच्छी जगह के रूप में दिखाता है, साथ ही यह अनुधावी के कारीगरों की अनोखी क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। पांच दिन तक चले वॉच एंड ज्वेलरी मिडिल ईस्ट शो के 56वें वर्जन में कई और आकर्षणों में एक सोने की साइकिल भी शामिल है, जिसकी कीमत 1.5 मिलियन एडईटी बताई गई है। इस प्रदर्शनी में इटली, भारत, तुर्की, अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और मलेशिया के 500 से अधिक स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक, साथ ही 1,800 से अधिक डिजाइनर, निर्माता और उद्योग के पेशेवर भी शामिल हैं।

अब यह विवाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन चुका है। जिस प्रकार से यह मुद्दा महिलाओं की अस्मिता, सम्मान और संवेदना से जुड़ता दिख रहा है, उससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा के लिए यह स्थिति असहज बनती जा रही है, खासकर तब जब पार्टी पवन सिंह को दक्षिण बिहार में अपना लोकप्रिय चेहरा बनाकर 2025 के चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है।

संजय लक्खेता

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अभिनेता पवन सिंह एक बार फिर अपने निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ पर्सनल नहीं रहा, इसका सीधा असर उनकी राजनीतिक छवि और भाजपा की आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर पड़ सकता है। पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ लंबे समय से तलाक का मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन हाल ही में लखनऊ में हुए एक घटनाक्रम ने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। अब यह विवाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन चुका है। जिस प्रकार से यह मुद्दा महिलाओं की अस्मिता, सम्मान और संवेदना से जुड़ता दिख रहा है, उससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा के लिए यह स्थिति असहज बनती जा रही है, खासकर तब जब पार्टी पवन सिंह को दक्षिण बिहार में अपना लोकप्रिय चेहरा बनाकर 2025 के चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है।

लखनऊ में हुए ताजा घटनाक्रम की बात करें तो ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर पहले ही यह घोषणा कर चुकी थीं कि वह अपने पति से मिलने लखनऊ जा रही हैं। उन्होंने लिखा था कि उन्हें उम्मीद है पवन सिंह उनसे जरूर मिलेंगे। लेकिन जब वह उनके घर पहुंचीं, तो वहां पुलिस पहले से मौजूद थी। न तो उन्हें घर में घुसने दिया गया और न ही पवन सिंह सामने आए। इस पूरी घटना का वीडियो खुद ज्योति सिंह ने रिकॉर्ड किया और उसे लाइव किया। वीडियो में ज्योति सिंह फूट-फूट कर रोती नजर आती हैं। वह कहती हैं कि अगर उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा तो वह इसी घर में जान दे देंगी। यह बयान और उनका दुखड़ा सुनकर सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गए। वीडियो वायरल हुआ और ज्योति सिंह के समर्थन में हजारों कमेंट आने लगे। यह विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहा। भोजपुरी सिनेमा के एक और बड़े नाम, खेसारी लाल यादव ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर भाभी ने कोई बड़ी गलती नहीं की है तो पवन सिंह को उन्हें माफ कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह भले ही

उनकी बहन नहीं हैं, लेकिन एक बेटी

हैं, और अगर उनकी अपनी बेटी के साथ ऐसा होता तो वह चुप नहीं बैठते। खेसारी लाल का यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत संवेदना नहीं, बल्कि इसमें सामाजिक और राजनीतिक संकेत भी छिपे हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच पहले से प्रतिस्पर्धा रही है, लेकिन अब यह प्रतिस्पर्धा केवल फिल्मी पर्दे तक सीमित नहीं रही, बल्कि सियासी रंग लेती नजर आ रही है। गौरतलब है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच तलाक का मामला बिहार के आरा की फैमिली कोर्ट में चल रहा है। पवन सिंह की ओर से बयान दर्ज हो चुका है, वहीं ज्योति सिंह की गवाही अभी होनी बाकी है। अगली सुनवाई की तारीख 8 अक्टूबर तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्योति सिंह ने इस तलाक के बदले 5 करोड़ रुपये और एक घर की मांग की है। जबकि पवन सिंह बच्चों की पड़ाई और खर्च उठाने को तैयार हैं, लेकिन दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। इस बीच ज्योति सिंह ने यह भी कहा है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो वह राजनीति में उतरकर अपनी लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह आगामी चुनावों में निर्दलीय या किसी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतर सकती हैं। यह बयान और परिस्थितियां भाजपा के लिए नई चिंता बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स का भाजपा की साइलेंट स्ट्रेंथ बता चुके हैं। ऐसे में अगर यह विवाद और गहराया, और महिलाओं में ज्योति सिंह के प्रति सहानुभूति की लहर चल पड़ी, तो भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस पूरे मामले में भाजपा की स्थिति बेहद नाजुक बन गई है। पार्टी के पास अब दो ही रास्ते हैं या तो वह पवन सिंह को सार्वजनिक रूप से विवाद सुलझाने को कहे और डैमज कंट्रोल करे, या फिर उन्हें बैकफुट पर डालकर कोई दूसरा चेहरा सामने लाएं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि भाजपा ने इस मुद्दे को हल्के में लिया, तो उसे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज्योति सिंह का यह कहना कि "यह सिर्फ मेरा अपमान नहीं, हर पत्नी और बहू का अपमान है", आम महिलाओं के दिल को छूने वाला बयान है।

जकार्ता में भारत U-23 की जीत

सुहैल भाट के दो गोलों ने इंडोनेशिया को दी मात



निज संबाददाता : जकार्ता के रोमांच से भरे गेलोरा बुंग कानों मछा स्टेडियम में 10 अक्टूबर, 2025 को खेले गए मैच में भारत की अंडर U-23 टीम ने जोश और जुझारू फुटबॉल का प्रदर्शन करते हुए इंडोनेशिया को 2-1 से हराया। यह मैच दो अलग-अलग हिस्सों की कहानी कहता है, जहां स्ट्राइकर सुहैल अहमद भाट मैच के हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने पहले ही हाफ में दो गोल दागे और ब्लू कॉल्ट्स के लिए जीत सुनिश्चित की।

पहले हाफ में जोरदार दबदबा

शुरुआती सीटी बजते ही भारत ने ऐसी तीव्रता के साथ खेल शुरू किया जिसने घरेलू टीम इंडोनेशिया को हिलाकर रख दिया। उनकी आक्रामक प्रेसिंग ने तुरंत ही परिणाम दिखाया और महज 5वें मिनट में सुहैल भाट ने एक ढीले इंडोनेशियाई पास पर कब्जा जमाया, बाक्स में घुसे और टॉप कॉर्नर में जोरदार शांट लगाकर गोल कर दिया। पीछे हटने की बजाय, भारत लगातार गोल के मौकों की तलाश में रहा। वे कई बार अपनी बढ़त बढ़ाने के करीब पहुंचे बिबिन मोहनन के जोरदार शांट को गोललाइन से हटाया गया और कोरोउ सिंह थिंगुजाम ने बाद में पोस्ट को हिला दिया। यह दबाव लगातार बना रहा और 26वें मिनट में दूसरा गोल आ गया। बिबिन की एक लो क्रॉस को कप्तान आयुष चेत्री ने स्मार्टली सुहैल भाट के लिए ते जाकर सेट किया। स्ट्राइकर ने

मैच की झलक
अंतिम स्कोर भारत U-23, 2-1 इंडोनेशिया
U-23 स्थान गेलोरा बुंग कानों मछा स्टेडियम,
जकार्ता भारत के गोलकर्ता सुहैल अहमद भाट (5वां, 26वां मिनट)
इंडोनेशिया के गोलकर्ता डोनी त्रि पमुगकस (41वां मिनट)

अपने मार्कर को रोके रखने की ताकत दिखाई और एक बार फिर नेट के टॉप कॉर्नर में जोरदार प्रहार किया। भारत के दबदबे के बावजूद, हाफटाइम से ठीक पहले इंडोनेशिया को एक जीवन्तरेखा मिल गई। 41वें मिनट में, लेफ्ट-बैक डोनी त्रि पमुगकस ने बाक्स के किनारे जगह बनाई और एक शानदार कर्ब्ड शांट टॉप कॉर्नर में लगाया, जिसे डेब्यू कर रहे गोलकीपर मोहनराज भी नहीं रोक सके।

दूसरे हाफ की जुझारू लड़ाई

दूसरा हाफ एक अलग कहानी लेकर आया। इंडोनेशिया के कोच ने हाफटाइम पर कई बदलाव किए और मेजबान टीम नई ऊर्जा के साथ उतरी, बराबरी का गोल करने के लिए उन्होंने ज़्यादा पास पर कब्जा कर लिया। बढ़ते दबाव का सामना करते हुए, भारत की डिफेंस दूसरे हाफ की मुख्य विशेषता बनकर उभरी। बैकलाइन, जो पहले हाफ में पैनी नज़र आ रही थी, और

भी जुझारू हो गई। राइट-बैक रिकी मीतेई जैसे खिलाड़ियों ने डिफेंस और अटैक दोनों में अहम भूमिका निभाई, जबकि हर्ष पालंदे ने अपनी फिजिकल प्रेजेंस से इंडोनेशिया के हमलों को विफल किया। भारत के पास अभी भी मैच पर मुहर लगाने के मौके थे, 57वें मिनट में इंडोनेशियाई गोलकीपर ने सुहैल भाट के हैट्रिक के मौके को बर्बाद कर दिया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, ब्लू कॉल्ट्स डटे रहे और इंडोनेशिया के हर हमले को विफल करते हुए एक कठिनाई से भरी और पूरी तरह से योग्य जीत हासिल की। मैदान से आवाज़ें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, दो गोल करने वाले हीरो सुहैल भाट ने अपना प्रदर्शन टीम को समर्पित किया। भाट ने कहा-“हम सब जीत के इरादे से यहां आए थे। एएफसी (U-23 एशियन कप क्वालीफायर) में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन दुर्भाग्य से, हम क्वालीफाई नहीं कर सके। फिर भी, जोश बरकरार है। हम और जीतना चाहते हैं यह सिर्फ एक शुरुआत है। हेड कोच नौशाद मूसा ने सामूहिक प्रयास की सराहना की। मूसा ने कहा- यह एक मुश्किल मैच था, लेकिन मैं वाकई में लड़कों की सराहना करता हूं। हर कोई पूरे मैच में एक-दूसरे का समर्थन कर रहा था। आगे कहा-अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हां, मैंने पहले ही कहा था कि इंडोनेशिया के लिए यह आसान नहीं होगा।

मनोरंजन

दुनिया के मंच पर भारत की बेटी ने रचा इतिहास

शैरी सिंह ने जीता मिसेज यूनिवर्स-2025 का ताज

48 साल में भारत को मिला पहला खिताब

निज संबाददाता : दुनिया के मंच पर भारत की बेटी ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। शैरी सिंह को मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया गया है और यह भारत की इस प्रतियोगिता में पहली जीत है। बता दें, इस जीत के साथ भारत ने यह प्रतियोगिता शुरू होने के 48 सालों बाद मिसेज यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया है। यानी पहली बार भारत ने इस प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता में विजय का मुकुट पहना है। 48वीं मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले फिलीपींस की राजधानी मनीला के खूबसूरत ओकाडा होटल में



कोलकाता में ‘कंटारा: चैप्टर वन’ की शानदार और मार्मिक स्क्रीनिंग

निज संबाददाता : कोलकाता के एक थिएटर में कंटारा : चैप्टर वन की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फिल्म प्रेमी शामिल हुए। ऋषभ शेठ्टी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2022 की ब्लॉकबस्टर कंटारा का प्रीकृत है, जिसने पूरे भारत में सांस्कृतिक हलचल मचा दी थी। अपनी पूर्ववर्ती फिल्म की तरह, हाल ही में रिलीज़ हुई यह फिल्म पौराणिक कथाओं, भावनाओं और अदुल दृश्यों का एक सशक्त मिश्रण है, जो मूल फिल्म में दर्शाई गई रहस्यमयी दुनिया की उत्पत्ति पर प्रकाश डालती है। तुषावनी छायांकन, तीव्र पृष्ठभूमि संगीत और मार्मिक अभिनय के साथ, कंटारा: चैप्टर वन उस लोककथा और आध्यात्मिक सार



को सफलतापूर्वक गहरा करती है जिसने इसकी पूर्ववर्ती फिल्म को इतना खास बनाया था। आलोचकों ने टिप्पणी की है कि फिल्म की कहानी धीमी शुरुआत करती है, लेकिन दूसरा भाग एक शक्तिशाली भावनात्मक प्रभाव और एक

यादगार चरमोत्कर्ष प्रदान करता है। पहली फिल्म कंटारा आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बेहद सफल रही थी। कम बजट में बनी होने के बावजूद, इसने दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की और कई राष्ट्रीय फिल्म

पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म और ऋषभ शेठ्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शामिल हैं। तटीय कर्नाटक की समृद्ध विरासत और उसकी गहरी सांस्कृतिक कहानी को उजागर करने के लिए फिल्म की सराहना की गई। कोलकाता में जनरेशन-जी दर्शकों ने इस विशेष स्क्रीनिंग का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। दर्शकों ने अभिनय, संगीत और निर्देशन की प्रशंसा करते हुए इसे दृश्यात्मक रूप से अद्भुत और आध्यात्मिक रूप से मार्मिक अनुभव बताया। सोशल मीडिया पर सकारात्मक समीक्षाओं की भरमार रही। कई लोगों ने इसे कंटारा परंपरा का एक सशक्त विस्तार बताया।

सादगीपसंद शख्सियत एपीजे अब्दुल कलाम की यादगार विरासत

गोविन्द अग्रवाल



भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति ही नहीं, शीर्षस्थ वैज्ञानिक, विचारक, देशभक्त और अनुसरणीय शिक्षाविद् होने के नाते सदियों याद किये जायेंगे। सादगीपसंद कलाम के जनहित में किये गये कार्य उन्हें बतौर आदर्श व्यक्तित्व पहचान कराता है। 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे के एक मध्यमवर्गीय तमिल परिवार में जन्मे उनके पिता जैनुलाब्दीन अधिक पढ़े-लिखे न होने पर भी तरक्कीपसंद थे। डॉ. कलाम ने अपने पिता से ईमानदारी, उदारता, भाईचारा, कृतज्ञता, समय की महत्ता व सादा जीवन जैसे गुणों को अपनाना सीखा। धार्मिक प्रवृत्ति की माता आशियम्मा से डॉ. कलाम ने ईश्वर में आस्था, जिम्मेदारियों का निर्वाह, अनुशासन, त्याग,



समर्पण जैसे मानवीय गुणों को सीखा। अब्दुल कलाम अपने तीन बड़े भाई और एक बड़ी बहन के परिवार में छोटी उम्र से ही परिवार की मदद करने के लिए भी अखबार बेचा करते थे। स्कूली दिनों में पढ़ाई में सामान्य होते हुए भी नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। गणित में तो उनकी विशेष रुचि थी। उनके अंतरंग मित्र जलालुद्दीन व शमसुद्दीन का डॉ. कलाम के बाल्यजीवन पर गहरा प्रभाव

रहा। जिनके साथ वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करते थे। जलालुद्दीन डॉक्टर कलाम को हमेशा वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताया करते थे। जिन्होंने डॉक्टर कलाम को सीमित दायरे से बाहर निकाल कर नई दुनिया का बोध कराया। इन दोनों के अलावा वे अपनी बहन जोहरा से भी बहुत प्रेरित थे, जिन्होंने हर कठिन

परिस्थितियों में अपने भाई को आगे बढ़ने में साथ दिया। अपने माता-पिता, शिक्षक एवं मित्रों के अलावा एपीजे अब्दुल कलाम प्रो. विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश, प्रोफेसर एन जी के मेनन और डॉ. राजारामन्ना के प्रति ताज़िदगी एहसानमंद रहे। एपीजे अब्दुल कलाम भारतरत्न एमएस सुब्रह्मण्यमी को अपनी दूसरी मां मानते थे। जिन्हें 1950 में तंजौर में त्यागराज समारोह में सुनने के बाद कलाम साहब मानने लगे कि किसी भी राग का उद्देश्य श्रोता के मन को ईश्वर एवं उसकी समस्त सृष्टि की ओर उन्मुख रखना है। कहना न होगा कि बिंग्स ऑफ फायर, इग्राइटेड माईंड्स और इंडिया 2020 सरीखी प्रेरक पुस्तकों के रचयिता मिसाइल मैन डॉ. कलाम ने पुस्तकों की रॉयल्टी का बड़ा हिस्सा स्वयंसेवी संस्थाओं और आपदा राहत कार्यों में दान कर दिया था।

स्मृति मंधाना बनीं 5000 वनडे रन बनाने वाली पांचवीं बल्लेबाज़

सबसे तेज़ उपलब्धि हासिल कबने वाली पहली महिला खिलाड़ी

शुभांशु राय

स्मृति मंधाना ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप मैच में एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया, जब वह एक कैलेंडर वर्ष में 1000 वनडे रन बनाने वाली इतिहास की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं। उप-कप्तान मंधाना को यह मौल का पत्थर हासिल करने के लिए सिर्फ 18 रन की जरूरत थी, जो उन्होंने सोफी मोलिन्याक्स की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर पूरा किया। इसी मैच में मंधाना ने महिला वनडे में 5000 रन पूरे करने वाली पांचवीं बल्लेबाज़ बनने का गौरव भी हासिल किया, जब उन्होंने विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 रन बनाते हुए यह उपलब्धि पाई। वह यह मुकाम हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ महिला बल्लेबाज़ भी बनीं। उन्होंने सिर्फ 112 पारियों में यह कारनामा किया। पिछले मैच में दक्षिण



अफ्रीका के खिलाफ मंधाना ने महिला विश्व कप मुकामबले के दौरान एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 29 वर्षीय मंधाना ने आयाबोंगा खाका की गेंद पर छक्का लगाकर 1997 में बेलिंडा क्लार्क द्वारा बनाए गए 970 रनों के रिकॉर्ड को पार किया। बाएं हाथ की यह बल्लेबाज़ अपने तीसरे वनडे विश्व कप में खेल रही हैं। वह 2017 के इंग्लैंड में हुए संस्करण में उपविजेता रही भारतीय टीम का हिस्सा भी थीं। इन रिकॉर्ड्स के बावजूद, मंधाना का इस विश्व कप में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 8, पाकिस्तान के खिलाफ 23 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 23 रन बनाए हैं। पहले दो मैचों में भारत को जीत मिली, लेकिन शीर्ष क्रम की नाकामी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सामने आई, जब भारत को तीन विकेट से हार झेलनी पड़ी।

पेज 1 का शेष.... क्यों सवालियों के घेरे में

महिलाओं को लघु उद्यम चलाने में सहायता दी जाती है। इससे उनमें नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन कौशल का विकास हुआ है। आत्मनिर्भरता और महिला उद्यमिता ऐसे प्रयासों से महिलाएं आर्थिक मजबूती के साथ आत्मसम्मान हासिल कर रही हैं। उनके अंदर प्रबंधन और निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण यह है कि महिलाओं का योगदान केवल आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों तक सीमित न रहकर सांस्कृतिक और नैतिक निर्माण में भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। सेविका समिति की शाखाओं और शिविरों में बालिकाओं को भारतीय शास्त्र, परंपरा और इतिहास से परिचित कराया जाता है। मां भारती और नारी गरिमा की अवधारणा गीतों, नाटकों और व्याख्यानों के माध्यम से भावनात्मक रूप से जोड़ी जाती है। यह प्रशिक्षण उन्हें परिवार और समाज दोनों के प्रति जिम्मेदारी निभाने की दिशा में सजग बनाता है और उनमें नेतृत्व के साथ-साथ अनुशासन की भावना को भी प्रगाढ़ करता है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक काल की प्राकृतिक आपदाओं तक, संघ प्रेरित महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सेविका समिति की महिलाएं राहत कार्य, भोजन वितरण, आश्रय केंद्र संचालन और चिकित्सा सहयोग जैसे कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देती रही हैं। यह उनकी सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भाव की जीवंत मिसाल है। उधर, आलोचक कहते हैं कि यदि महिला और पुरुष समान हैं तो महिलाओं को संघ की मुख्य संरचना में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। उनका मत है कि महिला नेतृत्व को पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। लाखों महिलाएं इन प्रयासों से आत्मबल और आत्मसम्मान प्राप्त कर रही हैं। हालांकि आलोचनाएं यह कहती हैं कि संघ की केन्द्रीय नीति निर्धारण इकाई में महिला नेतृत्व का अभाव अब भी दिखता है। फिर भी यह वास्तविकता भी है कि महिला शक्ति को स्वतंत्र मंच देकर उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय किया गया है। आज गांव-गांव और शहर-शहर में संघ प्रेरित सेविकाएं समाज सेवा, संस्कार शिक्षा और महिला उत्थान का दीप जला रही हैं। उनका योगदान शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति की मजबूत नींव रख रहा है और यह सिद्ध कर रहा है कि राष्ट्र की शक्ति स्त्री और पुरुष दोनों की साझेदारी से ही संपूर्ण होती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर राष्ट्र के संकट काल तक, महिलाओं ने बहादुरी से भूमिका निभाई। संघ मानता है कि मातृशक्ति ही राष्ट्र की जननी है। इतिहास में क्रांति और जागरण के क्षणों में महिलाओं का योगदान सबसे अधिक रहा है।

आज भी राष्ट्रीय संकट या प्राकृतिक आपदा के समय संघ व सेविका समिति की महिलाएं राहत और सेवा कार्यों में सक्रिय दिखाई देती हैं। बाढ़, भूकम्प, महामारी और दंगों के समय स्वयंसेविकाओं ने राहत शिविर चलाये, भोजन बाँटा और पीड़ित बहनों की सहायता की है। संघ पर महिला नेतृत्व को संगठनात्मक ढांचे में कम स्थान देने का आरोप लगता है। इसका कारण यह है कि संघ की मूल शाखा में केवल पुरुष सदस्य होते हैं। आलोचकों का कहना है कि यदि महिलाएं वास्तव में बराबर की भागीदार हैं, तो उन्हें इसी संरचना में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। संघ इस पर स्पष्ट जवाब देता है कि पुरुष और महिला दोनों की प्रकृति में अंतर है। इसलिए उनके विकास के लिये अलग-अलग मंच बनाना अधिक उपयुक्त है। राष्ट्र सेविका समिति इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। संघ का कहना है कि समिति स्वतंत्र रही है और उसकी अपने कार्यक्रम और दिशा तय करने की पूरी स्वतंत्रता दी गयी है। संघ का यह दावा भी है कि यदि महिला कार्यकर्ताओं को देखा जाए, तो वे सामाजिक उत्थान में पुरुषों से कहीं अधिक सक्रिय और प्रभावशाली ढंग से कार्य करती हैं। संघ ने महिला सशक्तिकरण के लिये क्या काम किया, इसके उदाहरण भी मौजूद हैं। संघ प्रेरित अनेक महिला कार्यकर्ताओं ने समाज में उल्लेखनीय काम किया है। आदिवासी क्षेत्रों में सेकड़ों संघ सेविकाएं शिक्षा का दीपक जलाने का कार्य कर रही हैं। शहरी सुगियों में बालिकाओं के लिए चलाये जा रहे संस्कार केंद्र वहां की पीढ़ी को नयी दिशा दे रहे हैं। अनेक महिलाएं ग्राम विकास योजनाओं की अगुआई कर रही हैं। संघ साफ कहता है कि राष्ट्र निर्माण में महिला और पुरुष दोनों की बराबर भागीदारी आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात पर जोर देता रहा है कि महिला 'शक्ति' और 'संस्कार' राष्ट्र की धुरी है। यही कारण है कि संघ ने शिक्षण, स्वास्थ्य, सेवा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में महिलाओं के लिए हजारों योजनाएं चलाई। हालांकि, आलोचनाएं भी कम नहीं हैं।बहरहाल, यह सच है कि संघ की केन्द्रीय नेतृत्व संरचना में महिलाओं की औपचारिक भागीदारी नहीं है। लेकिन संघ यह मानता है कि अलग मंच बनाकर महिलाओं को राष्ट्रसेवा के लिए स्वतंत्र अवसर देना ही वास्तविक सम्मान है। अंततः यह कहना उचित होगा कि महिलाएं आज संघ प्रेरित प्रयासों से गांव-गांव और शहर-शहर में आत्मविश्वास और सम्मान के साथ खड़ी हो रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है।

